बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 166 ● नई दिल्ली ● वीरवार 16 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली के लोक नायक भवन को मिली बम से उड़ाने की धमकी, इमारत कराई गई खाली

नई दिल्ली । दिल्ली स्थित लोक नायक भवन को बुधवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिसके बाद परिसर को खाली कराया गया और कई आपात दलों को तैनात किया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी। डीएफएस ने बताया कि दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर धमकी से संबंधित सूचना उसे दी गई जिसके बाद दमकल की एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस ने कहा कि उसने भी अपनी टीम भेजी है जिसमें श्वान और बम निरोधक दस्ते शामिल हैं जो इमारत की अच्छी तरह से तलाशी ले रहे हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली करा लिया गया है।

राघव चड्ढा ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, सौरभ भारद्वाज ने अशोक मित्तल पर ईडी के छापे और जेड+ सुरक्षा पर पूछा सवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की जेड प्लस सुरक्षा को जहां पंजाब सरकार नेक वापिस ले लिया है। वहीं, आप ने सौरभ भारद्वाज ने संभावना जताई है कि केंद्र की भाजपा सरकार राघव को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया करवा सकती है।

वहीं, उन्होंने राघव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भाजपा के कहने पर पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखे अपने पोस्ट में कहा है, बीजेपी सरकार का टूलबॉक्स इतना प्रेडिक्टेबल है। राघव चड्ढा पर ईडी ने दबाव बनाया, तो डर या लालच में उन्होंने अपनी ही पार्टी (जिसने उन्हें सांसद बनाया) की पीठ में छुरा घोंप दिया।

बताया- अशोक मित्तल क्यों मारा छापा

उन्होंने आगे कहा कि जब सोशल मीडिया पर राघव की आलोचना होने लगी, तो बीजेपी वाले उनके बचाव में उतर आए हैं। आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाकर उनकी जगह अशोक मित्तल को बना दिया। अब ईडी ने राघव को छोड़कर अशोक मित्तल पर छापा मार दिया। उनके घर और बिजनेस पर रेड की गई।

क्यों राघव को केंद्र सरकार ने दी Z+ सिक्योरिटी

सौरभ ने कहा, केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सुरक्षा दे दी। सबकुछ इतना आपस में जुड़ा हुआ लग रहा है। बीजेपी सरकार इतनी बेताब हो गई है कि राघव चड्ढा के लिए आप सांसद अशोक मित्तल पर ईडी से छापेमारी करवा रही है।

क्या आप और राघव चड्ढा के बीच का विवाद

बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने भले ही अपनी पोस्ट में राघव चड्ढा को Z+ सुरक्षा मिलने की बात कही है लेकिन खबर लिखे जाने तक इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) और रायसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पहले पार्टी ने उन्हें रायसभा में उपनेता पद से हटाया और अब पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली है। इस घटनाक्रम ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की महंगाई भत्ता विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई 6 मई को

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन के लिए दायर याचिक पर बुधवार को सुनवाई टल गई। सरकार ने कर्मचारियों के डीए पेमेंट की समय सीमा बढाने की मांग की है लेकिन इस मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल के लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि उन्होंने कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कई कदम पहले ही उठा लिए हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दलील रखते हुए कहा कि कमेटी की सिफारिशों को मान लिया गया है और करीब 6000 करोड़ रुपये का भुगतान कर्मचारियों को किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि कमेटी ने बाकी बचे मामलों की जानकारी इकट्ठा करने और आगे भुगतान करने की प्रक्रिया जारी रखने को कहा है, जिस पर सरकार काम कर रही है। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। उन्होंने अदालत में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी 2026 को एक अहम आदेश देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 के बीच के महंगाई भत्ते के बकाये का 25 प्रतिशत हिस्सा 31 मार्च तक देने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने बाकी 75 प्रतिशत भुगतान के लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा कर रही हैं। इस कमेटी में तीन पूर्व जज शामिल हैं, जिन्हें यह तय करना है कि बाकी राशि का भुगतान कैसे और कब किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा था कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

दिल्ली के आईटीओ चौक पर खत्म होगी जाम की समस्या, सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली।

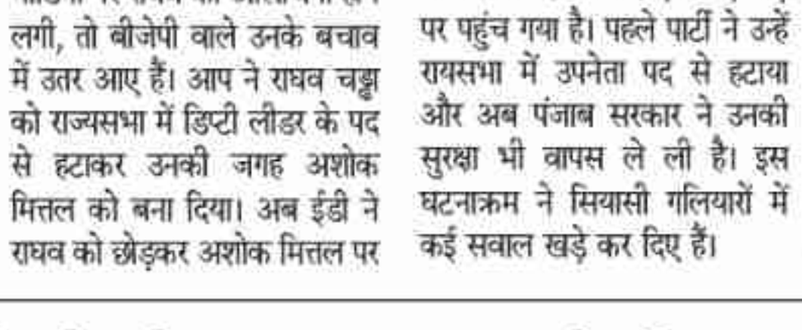

सब कुछ ठीक-ठाक ठाक रहा तो आने वाले समय में आईटीओ चौक पर लोगों को जाम से कुछ राहत मिल सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गत दिनों बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से इस चौराहे पर जाम की समस्या कम करने के बारे में पूछा है, उन्होंने जानकारी ली कि यहां के जाम को दूर करने के लिए क्या काम हो रहा है। उसके बाद से अधिकारी हरकत में हैं। जल्द ही इसे लेकर अधिकारियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें यातायात पुलिस के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। भाजपा सरकार आने के बाद इस चौक पर जाम को लेकर व्यवहार्यता अध्ययन के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर काम चल रहा है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चौक पर जाम काम करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। आईटीओ चौक पर फ्लाईओवर बनाकर इसे आईपी एस्टेट फ्लाईओवर से जोड़ने की योजना भी प्रमुख रूप से शामिल है। प्रतिदिन छह लाख से अधिक वाहन यहां से आवागमन करते हैं। योजना के तहत एलिवेटेड रोड को डीडीयू मार्ग पर हिंदी भवन की लालबत्ती से आईटीओ चौक पास करते हुए रिंग रोड पर बने आइपी एस्टेट फ्लाईओवर से जोड़ने की योजना है। इसके अलावा यमुनापार से डीडीयू मार्ग आने-जाने के लिए फ्लाईओवर के दोनों ओर रैंप उतारे जाने हैं, जो विकास मीनार के पास से शुरू होकर डीडीयू मार्ग पर हिंदी भवन के पास नीचे उतरेंगे। इसके अलावा चौराहे से तिलक ब्रिज की ओर आना-जाना भी सुगम किया जाना भी योजना में शामिल है। आईटीओ चौराहे पर प्रमुख सरकारी कार्यालय हैं, जिसमें आइसीएआई, आयकर कार्यालय, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय, बिक्री एवं कर विभाग मुख्यालय, डीडीए का विकास मीनार भवन, एजीसीआर बिल्डिंग और कई प्रकाशन कार्यालय आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। भूमिगत मेट्रो तिलक ब्रिज से दिल्ली गेट (बहादुर शाह जफर मार्ग) की ओर चौराहे को पार करती है। बहादुर शाह जफर मार्ग और विकास मार्ग के दोनों तरफ की सड़कों पर भारी यातायात होता है। बड़ी संख्या में कार्यालय, आईटीओ मेट्रो स्टेशन और चार बस स्टैंड के कारण यहां से बड़ी संख्या में पैदल यात्री भी गुजरते हैं। आईटीओ चौराहे पर फ्लाईओवर के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत दो अप्रैल और नौ अप्रैल को बैठक हुई थी। मुख्य सचिव के निर्देश पर 28 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने योजना स्थल का निरीक्षण किया था। टीम ने मौके की स्थिति को देखते हुए कई तकनीकी पहलुओं को लेकर भी विचार-विमर्श किया है, जिसमें भूमिगत मेट्रो लाइन होने का एक पहलू भी शामिल है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राबर्ट वाड्रा को समन, 16 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली।राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी राबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपितों को समन जारी किया है। कोर्ट ने वाड्रा और अन्य आठ आरोपितों को 16 मई को पेश होने का निर्देश दिया है। अब कोर्ट द्वारा समन जारी होने के बाद मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी, जहां सभी आरोपितों को पेश होना होगा। यह समन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद जारी किया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि फिलहाल जांच का दायरा सीमित है और इस चरण में केवल तकनीकी पहलुओं, विशेषकर क्षेत्राधिकार से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। अन्य तर्कों पर आरोप तय होने के दौरान सुनवाई की जाएगी। यह मामला वर्ष 2018 में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें वाड्रा के साथ हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा समेत अन्य को नामजद किया गया था। आरोपों में भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी जैसी धाराएं शामिल हैं। ईडी के अनुसार, वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर इलाके में 3.5 एकड़ जमीन ओमकारेश्वर प्रापर्टीज से करीब 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी।

बाद में इसी जमीन को रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को करीब 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। एजेंसी को संदेह है कि इस सौदे में हुई भारी कमाई मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा हो सकती है, जिसके चलते धन के स्रोत और लेनदेन की जांच शुरू की गई। ईडी ने 17 जुलाई 2025 को दाखिल पूरक अभियोजन शिकायत में राबर्ट वाड्रा को औपचारिक रूप से इस मामले में आरोपित बनाया था।

द्वारका टनल के ऊपर बनी सड़क से एनएच-8 तक जल्द फर्राटा भर सकेंगे वाहन, ट्रैफिक पुलिस ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली । द्वारका इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। सेक्टर-21 पैसिफिक मॉल के पास स्थित एलिफेंट चौक से एनएच-8 तक सड़क को नए तरीके से तैयार किया जा रहा है, इससे यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत एलिफेंट चौक पर लगी हाथियों की मूर्तियों को हटा दिया गया है और सड़क का नया अलाइनमेंट तैयार किया है। अब इस रास्ते से वाहन सीधे द्वारका टनल के ऊपर बनी सड़क (सरफेस रोड) से होते हुए एनएच-8 तक जा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने इस मुद्दे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सामने उठाया था। लगातार प्रयासों और बातचीत के बाद एनएचएआई इस बदलाव के लिए तैयार हुआ। इसके बाद तेजी से काम शुरू हुआ और अब सड़क पर डामर बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस व्यस्त इलाके में जाम कम करना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस काम को ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) शिव कुमार और एसीपी ट्रैफिक रविंदर पंडित की निगरानी में शुरू किया गया। टीआई ने इस योजना पर गहन अध्ययन के बाद सुझाव दिया था, जिसे बाद में एनएचएआई और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से लागू किया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह नया रास्ता अगले 10 से 15 दिनों के अंदर यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही, चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का काम भी किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक और बेहतर तरीके से नियंत्रित हो सकेगा। वहीं, द्वारका सेक्टर-22 स्थित क्लासिक अपार्टमेंट के अध्यक्ष जेबी कौशिक ने बताया कि यातायात पुलिस ने 'प्रोजेक्ट संगम' शुरु किया है। संगम यानी सिस्टमेटिक एक्शन एंड नेटवर्क गवर्नेंस फॉर एरिया मोबिलिटी नामक पहल के तहत वह रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के साथ मीटिंग करती है। ऐसे में एक बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था, जिसे स्वीकार लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित था और अब इसके पूरा होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस इलाके में पहले अक्सर जाम लगता था और कई वाहन चालक गलत दिशा में गाड़ी चलाने लगते थे, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। नए अलाइनमेंट के बाद इन समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है। यह काम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के प्रोजेक्ट संगम के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट में शहर के अलग-अलग इलाकों में ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं को पहचानकर उनका समाधान किया जा रहा है।

एसीपी ट्रैफिक रविंदर पंडित ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि सड़कों पर सुगम और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद द्वारका के इस व्यस्त मार्ग पर रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

आपूर्ति को रखा बरकरार

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद पूरी दुनिया की चिंता ऊर्जा को लेकर थी। आज की दुनिया ऊर्जा के लिए जीवाश्म तेलों पर सबसे ज्यादा निर्भर है, जिसे हम पेट्रोल और डीजल के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस भी आज ऊर्जा की बड़ी स्रोत है। ईरान पर हमले के पहले बहुत लोगों ने होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज हर पढ़ा-लिखा और सचेत शख्स इसे जान गया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित इस संकरे समुद्री रास्ते पर ईरान का कब्जा है। इसके जरिए पूरी दुनिया को आपूर्ति होने वाला बीस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ इसी रास्ते से गुजरता रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो ईरान पर हमले के पहले तक भारत आयात होने वाले कच्चे तेल के आधे हिस्से की आपूर्ति इसी रास्ते होती थी। इससे भारत की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक थी। लेकिन भारत ने ना सिर्फ होर्मुज के जरिए अपनी आपूर्ति को बनाए रखने की कूटनीतिक कोशिशें जारी रखीं, बल्कि वैकल्पिक रास्ते की भी तलाश तेज कर दी। भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का करीब 85 फीसद हिस्सा आयात करता है। इसका आधा हिस्सा होर्मुज के रास्ते ही आता था। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार होर्मुज के रास्ते भारत रोजाना ढाई से 2.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता था। लेकिन ईरान पर हमले के बाद यह घटकर इसका आधा ही रह गया है। वैसे तो होर्मुज पर ओमान का भी दावा माना जाता है, लेकिन हकीकत में इस जलमार्ग पर पूरी तरह ईरान का दबदबा है। हमले के बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इस रास्ते पर ना सिर्फ निगरानी बढ़ा दी है, बल्कि सीमित आवाजाही को ही मंजूरी दी है। भारत को इसकी आशंका थी, इसलिए उसने खाड़ी के देशों से तेल आयात के लिए वैकल्पिक मार्गों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। संकट के क्षण में भले ही ईरान ने भारत के प्रति सहयोगी रूख अख्तियार कर रखा है, लेकिन भारत ने 'केप ऑफ गुड होप' यानी अफ्रीका के दक्षिण से गुजरने वाले जलमार्ग का भी उपयोग बढ़ा दिया है। इस बीच भारत ने कूटनीतिक प्रयास जारी रखा। इसका असर यह हुआ कि ईरान भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे रहा है। एलपीजी लदा एक जहाज कोचीन आ चुका है और ऐसे ही कुछ और जहाज तेल और गैस लेकर भारत आ रहे हैं। इस बीच भारत ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को अपनी नौसेना के जरिए सुरक्षा दे रहा है। भारत सरकार के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। इस बीच भारत ने रूस से भी कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति बढ़ा दी है। इसका असर यह हुआ है कि भारत में जिस तरह की महंगाई की आशंका थी, वैसी नहीं दिखी। हालांकि उद्योगों के लिए आपूर्ति किए जाने वाले व्यवसायिक गैस सिलिंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और व्यवसायिक गैस की आपूर्ति कम होने के चलते खाने-पीने वाली चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। महानगरों में सर्वसुलभ ठेले की चाय की कीमतें डेढ़ गुनी तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन आपूर्ति श्रृंखला जारी रहने के चलते स्थिति खराब नहीं हुई है। जबकि पड़ोसी पाकिस्तान में आधी गाड़ियों को ही सड़कों पर उतरने की अनुमति है, वहां पेट्रोल भारत के मुकाबले करीब ढाई गुनी ऊंची दर पर मिल रहा है। पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद कूटनीति की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाले हुए युद्ध शुरू होने के महज 48 घंटों के भीतर आठ खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत,ओमान, कतर, जॉर्डन, ओमान, बहरीन और इजरायल के नेताओं से बात की। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की। इस बातचीत का मकसद वैश्विक हालात पर चर्चा के साथ ही भारतीय हितों को सुनिश्चित करना भी था। इस बीच 'गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल' के महासचिव जासेम मोहम्मद अल बुदैवी से फोन पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बात की है। इस बातचीत का मकसद खाड़ी देशों के इस संगठन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के साथ ही भावी ऊर्जा संकट से भारत को मुक्ति दिलाने को लेकर रणनीति बनाना भी है। इसके पहले मंत्री हरदीप पुरी ने कतर की यात्रा की थी। दरअसल भारत इन देशों से भी पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बढ़ाना चाहता है। भारत की कोशिश ईरान के विकल्प के रूप में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों का भी सहयोग हासिल करने की है। भारत को अपनी खेती के लिए रासायनिक खाद की भी जरूरत पड़ती है। भारत में खाद उत्पादन के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बेशक रूस से भारत को कच्चा तेल और खाद की सामग्री मिल रही है, लेकिन भारत की कोशिश आपूर्ति को विविधरंगी बनाए रखना है। इसकी वजह यह है कि किसी एक देश पर किसी खास आयात के लिए पूरी तरह निर्भर होना भविष्य में ब्लैकमेलिंग की वजह बन सकता है। भारत के पास आज करीब साठ करोड़ का ऐसा विशाल मध्य वर्ग है, जिसकी खरीद क्षमता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शायद ही कोई उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादक देश ऐसा होगा, जिसे भारत की जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन भारत की अपनी जरूरतें भी हैं और यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में अगर किसी चीज की गंभीर कमी होती है तो अफरातफरी का माहौल उत्पन्न होना आसान हो जाता है। इससे महंगाई भी बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से लोक के बीच नाराजगी बढ़ती है और फिर यह गुस्सा राज व्यवस्था के खिलाफ आंदोलनों के रूप में मुखर होता है।

जंगल एक यात्रा, जो बाहर से शुरू होकर भीतर अनंत गहराइयों तक पहुँचती है

इस बार कहीं अलग चलते हैं?..... यात्रा अक्सर इसी छोटे से सवाल से जन्म लेती है। पर कुछ यात्राएँ सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होतीं, वे भीतर के शोर को सुनने, थमे हुए एहसासों को फिर से जगाने और खुद से मिलने का अवसर बन जाती हैं। जंगल...... ऐसी ही एक यात्रा है, जहाँ हर कदम किसी दृश्य की ओर नहीं, बल्कि एक अनुभव की ओर बढ़ता है। जब आप अचानकमार टाइगर रिजर्व जैसे किसी वन्य विस्तार में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है, वह है..... यहां की ठहरी हुई और गहराई असीम शांति का एहसास। यह साधारण शांति नहीं, बल्कि एक गहराई लिए हुए मौन है, जिसमें पक्षियों की पुकार, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं बहती नदी की धीमी ध्वनि मिलकर एक अद्भुत संगीत रचती हैं। शहरों के शोर से दूर, यहाँ प्रकृति अपने मूल रूप में सांस लेती दिखाई देती है। सुबह की पहली किरण जब घने सागौन और साल के वृक्षों के बीच से उतरती है, तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। हल्की धुंध के बीच से छनकर आती रोशनी, ओस से भीगी धरती और ताज़ी हवा...ये सब मिलकर मन को एक अजीब सी शांति से भर देते हैं। यही वह क्षण होता है जब इंसान महसूस करता है कि वह प्रकृति का हिस्सा है, उससे अलग नहीं। जंगल का सबसे रोमांचक पहलू है...उसकी अनिश्चितता। जिप्सी सफारी या फिर हाथी की सवारी के दौरान हर मोड़ एक नई उम्मीद लेकर आता है। कभी हिरणों का झुंड दिखाई देता है, कभी रंग-बिरंगे पक्षियों की उड़ान, और कभी अचानक सामने आ जाता है वह अद्भुत दृश्य-बंगाल टाइगर। बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा है-उसकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित और जीवित है। भारत में टाइगर रिजर्व केवल पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि संरक्षण के जीवंत उदाहरण हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत देशभर में कई संरक्षित क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जहाँ न केवल बाघों की रक्षा की जाती है, बल्कि पूरे जंगल और उसमें बसे जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। यह पहल हमें यह भी सिखाती है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक है।जंगल की असली खूबसूरती दिन के उजाले में ही नहीं, बल्कि रात की खामोशी में भी दिखती है। जब आसमान तारों से भर जाता है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तो लगता है जैसे पूरी प्रकृति किसी गहरे ध्यान में लीन हो। ऐसे क्षणों में, जब आप बोनफायर के पास बैठकर अपनों के साथ बातें करते हैं, तो हर छोटी-छोटी बात भी एक याद बन जाती है...एक ऐसी याद, जो जीवनभर साथ रहती है। अचानकमार टाइगर रिजर्व की वह सघन हरियाली और साल के ऊंचे वृक्षों के बीच से छनकर आती धूप केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक रूहानी अनुभव है। जब आप बिलासपुर की हलचल पीछे छोड़कर लोरमी मार्ग से होते हुए अचानकमार की गोद में प्रवेश करते हैं, तो शोर थम जाता है और संवाद शुरू होता है...प्रकृति के साथ और स्वयं के साथ।यह एक ऐसी यात्रा है जो इस अनुभव की गहराइयों को समेटने का प्रयास करता है।अचानकमार का जंगल जहाँ मौन बोलता है और समय ठहर जाता है। जैसे ही गाड़ी पहिए अचानकमार की सीमा को छूते हैं, हवा का मिजाज बदल जाता है। वह शहर की धूल भरी गर्म हवा नहीं, बल्कि आदिम गंध से भरी एक शीतल छुअन होती है। यहाँ साल (सरई) के दरख्त आसमान को छूने की जिद में खड़े हैं, मानो वे धरती और अंबर के बीच कोई प्राचीन संदेशवाहक हों। जंगल में प्रवेश करना ऐसा लगेगा मानो किसी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए हों। यहाँ हर कदम पर एक रहस्य है। बंदरों की कुलाचें, हिरणों की चौकन्नी निगाहें और हवा में तैरती पक्षियों की चहचहाहटें .... कहीं दूर से आती किसी जानवर की आवाज़ जंगल की शांत नीरवता को तोड़ती हुई आवाजें ये सब बताती हैं कि हम यहाँ अतिथि हैं, मालिक नहीं। जब जिप्सी कच्ची पगडंडियों पर धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, तो मन की सारी परतें एक-एक कर खुलने लगती हैं। वह भागदौड़, वह प्रतिस्पर्धा का तनाव और वह शब्दों का जाल, सब पीछे छूट जाता है। जंगल हमें सिखाता है धीमे चलना, ठहरना, और महसूस करना। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। सब कुछ अपने सबसे सच्चे रूप में होता है। शायद यही कारण है कि जो व्यक्ति एक बार जंगल की इस दुनिया में प्रवेश करता है, वह कुछ न कुछ बदलकर ही लौटता है। वह सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि एक एहसास अपने साथ ले जाता है.....एक ऐसा एहसास, जो उसे बार-बार उसी शांति की ओर खींचता है। कुल मिलाकर यही समझ में आता है कि यात्रा केवल नई जगह देखने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को नए सिरे से समझने के लिए होती है। और जंगल—वह एक ऐसा दर्पण है, जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। जंगल की यात्रा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह आपको अकेला नहीं करती, बल्कि आपको एकांत देती है। अचानकमार की उस अनंत नीरवता में जब आप अपनी ही सांसों की आवाज सुनते हैं, तब समझ आता है कि हम कृत्रिम दुनिया में कितने खो गए थे। मनियारी नदी के किनारे पत्थरों पर बैठकर जब आप बहते पानी को देखते हैं, तो वह केवल जल नहीं होता, वह जीवन की निरंतरता का प्रतीक बन जाता है। यहां न कोई पद होता है, न प्रतिष्ठा.....यहाँ आप केवल एक मनुष्य होते हैं, जो अपनी ही आत्मा की गहराइयों को टटोल रहा होता है। अचानकमार के जंगल में शाम का ढलना एक कविता जैसा है। सूरज जब पहाड़ियों के पीछे छिपता है, तो पूरा जंगल एक सिंदूरी चादर ओढ़ लेता है।

सम्पादकीय...

भविष्य की जिम्मेदारी

मानव सभ्यता केवल वर्तमान की उपलब्धियों से नहीं बनती, बल्कि वह अपने अतीत की स्मृतियों, परंपराओं और धरोहरों से आकार लेती है। 18 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व धरोहर दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी विरासत केवल पत्थरों से बने स्मारक नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी ऐतिहासिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैली ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन मंदिर, किले, स्मारक, पुरातात्विक स्थल और सांस्कृतिक परंपराएँ—ये सभी मिलकर मानव इतिहास की एक समृद्ध कहानी कहते हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ हर कदम पर इतिहास सांस लेता है, यह विरासत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता-एलोरा की गुफाएँ, साँची स्तूप—ये केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा के प्रतीक हैं। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि आज हमारी अनेक धरोहरें उपेक्षा, अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण खतरे में हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, अनियोजित विकास और जागरूकता की कमी ने इन अमूल्य धरोहरों को क्षति पहुँचाई है। कई बार हम इन स्थलों को केवल 'घूमने की जगह' मानकर उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को अनदेखा कर देते हैं। धरोहरों का संरक्षण केवल सरकार या पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। जब तक आमजन में इनकी महत्ता के प्रति जागरूकता नहीं होगी, तब तक संरक्षण के प्रयास अधूरे रहेंगे। हमें अपने बच्चों को इतिहास और संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाना होगा, ताकि वे इन धरोहरों को केवल अतीत का अवशेष नहीं, बल्कि भविष्य की धरोहर के रूप में देखें। इसके साथ ही, आधुनिक विकास और धरोहर संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना भी आवश्यक है। विकास की दौड़ में यदि हम अपनी जड़ों को ही नष्ट कर देंगे, तो हमारी पहचान खो जाएगी। इसलिए, यह जरूरी है कि योजनाएँ इस प्रकार बनाई जाएँ, जिनमें विकास और संरक्षण दोनों साथ-साथ चल सकें। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची तैयार करना और उनके संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश देना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल अंतरराष्ट्रीय मान्यता ही नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए एक वैश्विक जिम्मेदारी भी तय करता है। विश्व धरोहर दिवस हमें यह सिखाता है कि विरासत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। यदि हम अपनी धरोहरों को सहेजकर रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी और अपनी पहचान पर गर्व कर सकेंगी। धरोहरों को बचाना केवल इतिहास को बचाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बचाना है।

> **विश्व धरोहर दिवस हमें यह सिखाता है कि विरासत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। यदि हम अपनी धरोहरों को सहेजकर रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी और अपनी पहचान पर गर्व कर सकेंगी।**

गर्मियों में प्रकृतिक तरीके से रखें हाइड्रेशन

गर्मियों के मौसम में पसीने के कारण शरीर से जरूरी मिनरल्स और पानी तेजी से निकल जाते हैं जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाती है / इस मौसम में अपने शरीर को हाइड्रेट करने के लिए पानी के साथ हमें पानी वाले फल , नारियल पानी , नींबू पानी जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का सहारा भी लेना चाहिए हालाँकि कुछ लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सहारा लेते है जिनमे केमिकल और आर्टिफीसियल फ्लेवोर्स को मिलाकर एक उम्दा स्वाद तैयार किया जाता है और लोग अपने परिवार और मेहमानों को शौक से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिलाते है लेकिन इन ड्रिंक्स के लगातार उपयोग से शुगर और पेट सहित अन्य अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं / गर्मियों के मौसम में शरीर को तरोताजा रखने के लिए अनेक हेल्दी ड्रिंक्स उपलब्ध होते हैं जोकि शरीर में पानी की कमी दूर करते हैं और आपको अन्दर से मजबूत भी रखते हैं /

1 ---पानी -----

जब आपको प्यास लगे तो समझिये की शरीर में पानी की कमी पहले ही हो चुकी है / गर्मियों में जब भी आपका शरीर डिहाइड्रेट होना शुरू करता है तो आप आलसी और सुस्त महसूस करने लगते है / शरीर में तरल पदार्थों की हल्की सी कमी भी आपका मूड खराब कर सकती है एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए इसका कोई पैमाना तय नहीं है / यह आपकी ऊंचाई , वजन , जेंडर, सक्रियता और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है / स्वास्थ्य के माहिरों की माने तो एक आदमी को औसतन 8 -10 गिलास पानी पीना चाहिए/ गर्भवती महिलाओं को 10 गिलास पानी पीना चाहिए जबकि स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को कम से कम 12 गिलास पानी पीना चाहिए / दिन में हर दो घण्टे में एक गिलास पानी पीना चाहिए / आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक से परहेज करना चाहिए क्योंकि इसमें विद्यमान तत्व आपका शुगर का स्तर बढ़ा सकते हैं

और आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है / स्पोर्ट्स ड्रिंक उन लोगों को पीना चाहिए जोकि जिम आदि में लम्बे समय तक गहन एक्सरसाइज आदि करते हैं और जिन्हे पसीना आता है / पानी में कोई भी शुगर या कैलोरी आदि नहीं मिलाई जाती जिसकी वजह से आप दिन भर पानी पी सकते रहो / सादे पानी में खीरा , निम्बू ,पुदीना आदि मिलाकर इसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है जिससे इसे पीना सहज हो सकता है / इनके मिलाने से पानी में उचित पोषण और प्राकृतिक सुगन्ध का अहसास होता है तथा शरीर को डिहाइड्रेट करने का यह स्वादिष्ट तरीका भी है / खीरा , निम्बू ,पुदीना का उपयोग त्वचा को स्वास्थ्यवर्धक और आकर्षक बनता है /खीरे में लगभग 95 प्रतिशत पानी होता है और इसे प्रकृति ने सबसे यादा हाइड्रेटिंग फूड बनाया है / खीरे में विटामिन सी और के विद्यमान होते है जोकि त्वचा के संक्रमण को रोकते है और शरीर में कोलेजन उत्पादन को प्रमोट करते हैं पानी की बोतल हमेशा अपने नजदीक रखिये / दुबारा उपयोग में आने वाली पानी की बोतल अपने साथ रखिए ताकि इसे रिफिल किया जा सके

2- पानी वाले फल -----

गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी वाले फलों का सेवन बेहतर होता है क्योंकि इनमे प्रकृतिक शुगर , फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स मौजूद होते हैं / यह हाइड्रेशन के साथ साथ शरीर को गर्मी और सूरज की धूप से होने वाले नुकसान से भी सुरक्षा प्रदान करते है / यादातर फलों में पानी की अधिकता के साथ ही विटामिन , मिनरल और एंटीऑक्सिडेंट्स मौजूद होते हैं / तरबूज में 92 प्रतिशत पानी होता है जबकि स्ट्राबेरी में 91 प्रतिशत , खरबूजे में 90 प्रतिशत, और आड़ू में 89त्र पानी होता है / यह फल हाइड्रेशन के साथ ही शरीर को विटामिन सी , विटामिन ए , पोटैशियम आदि भी प्रदान करते हैं जिससे शरीर में ऊर्जा मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है ।

आप अपनी दिनचर्या में हल्का सा बदलाव करके इन फलों को रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं / आप फ्रूट सलाद या स्नैक्स बना कर सुबह के नाश्ते में ले सकते है / इन फलों को दही , दूध ,सब्जियों आदि में ब्लेंडर से पीस कर स्मूदी बना कर उपयोग कर सकते हो जिससे यह अधिक स्वास्थ्य वर्धक और पौष्टिक बनता है / दोपहर में इन फलों के स्लाइस मिड डे ब्रेक के दौरान ले सकते है / यादातर फलों का ही सेवन करें और अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हैं तो आधा कप बेहतर होगा / फ्रूट ड्रिंक या फ्रूट कॉकटेल में सोडियम और चीनी विद्यमान होती है / कोशिश करें की विभिन्न प्रकार के अलग प्रजातियों के कलर्ड फल ग्रहण करें क्योंकि इनमे न्यूट्रिशन की भरमार रहती है। अपने फ्रिज ने फलों का स्टॉक रखें ताकि यह आपको आसानी से उपलब्ध हों / दिन में दो बार पानी वाले फलों के सेवन की आदत डालें

3 -------नारियल का पानी-

नारियल पानी प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक पेय है जोकि शरीर को हाइड्रेट करता है जिससे आप उर्जावान और एक्टिव महसूस करते है / यह ना सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जो ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं/ नारियल पानी पीने से थकान और कमजोरी दूर होती है और यह पाचन क्रिया को भी सुधारता है/ नारियल पानी दिन के किसी भी समय पिया जा सकता हैए लेकिन आयुर्वेदाचार्य इसे सुबह खाली पेट पीने की सलाह देते हैं ताकि आपको इसका अधिकतम लाभ मिल सके / नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होते हैंए जो स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाने में मददगार है/ सुबह खाली पेट एक गिलास नारियल पानी पीने से त्वचा हेल्दी और आकर्षक बनती है / नारियल पानी में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है/ रोजाना एक गिलास नारियल पानी पीने से पेट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है / नारियल पानी में 94 प्रतिशत पानी की मात्रा होती है। ये शरीर को जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है / गर्मियों के महीने में आउटडोर एक्टिविटीज / स्पोर्ट्स आदि के बाद नारियल पानी का सेवन काफी लाभदायक माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को हाइड्रेटेड और उर्जावान रखने में मदद करते हैं।

4 ---छाछ

गर्मियों में पुदीना छाछ पीने से पेट शांत रहता है और पाचन क्रिया सही रहती है/ यह शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन दोनों प्रदान करता है/ इसमें प्रोटीन, कैल्शियमए और विटामिन बी 12 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ.साथ कमजोरी और थकान को भी दूर करते हैं/ छाछ में इलेक्ट्रोलाइट्स तत्व विद्यमान होते हैं जोकि शरीर के वाटर बैलेंस को बनाये रखने में मदद रखते हैं / छाछ में दूध और दही के मुकाबले पानी की मात्रा यादा होती है जबकि फैट और कैलोरी की मात्रा कम होती है / मोनोपौज के बाद जिन महिलाओं का स्वभाव चिड़ चिड़ा हो जाता है उन्हें नियमित रूप से एक गिलास छाछ का सेवन करना चाहिए / अगर छाछ के खट्टे स्वाद से आप परेशान रहते हों तो इसमें हल्के.फुल्के मसाले और काला नमक मिला कर आप इसे स्वादिष्ट बना लीजिये / छाछ को दोपहर के खाने के साथ पीना सबसे यादा हितकर माना जाता है / इस समय छाछ पीने से ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी से छुटकारा मिलता है/ हम अक्सर तला भुना या मसालेदार खाना खाते रहते है जिसकी वजह से शरीर के अन्दर का तापमान बढ़ जाता है /छाछ में प्रोबायोटिक्स तत्व मौजूद होते हैं और रोजाना 1 गिलास छाछ पीने से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है।

5 ------ आइस्ड हर्बल चाय-

गर्मियां आ गई है तो ऐसे में बार बार गरमा.गरम चाय पीना सेहत के लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है / ऐसे में आप एंटी.ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर हर्बल चाय ट्राई कर सकते है जोकि सेहत और स्वाद दोनों तरफ से बेहतर साबित होगी हर्बल चाय, खासकर मिंट और ग्रीन टी गर्मियों में बहुत फायदेमंद होती है/ यह न केवल शरीर को हाइड्रेट करती हैए बल्कि शांति और ताजगी भी देती है/ हर्बल चाय में शहद या कम चीनी का उपयोग करें ताकि यह यादा हेल्दी रहे/ हर्बल चाय के साथ साथ आप आइस्ड टी भी उपयोग कर सकते है जोकि आपको तरोताजा रखेगी / आइस्ड टी में हर्बल चाय के अतिरिक्त कुछ कूलिंग और रिफ्रेशिंग चीजों को भी शामिल किया जाता है। दिन में एक हर्बल आइस टी के सेवन से उच्च रक्तचाप , शुगर और तनाव को नियन्त्रित करने में मदद मिलती है / हर्बल आइस टी तुलसी, दालचीनी, मुलेठी, पुदीना , लौंग , काली मिर्च आदि से बनती है / आप कैमोमाइल, पिपरमिंट, या हिबिस्कस की आइस टी बनाकर भी पी सकते है। इससे ना केवल आप अधिक रिलैक्स फील करते हैं बल्कि पाचन के लिए भी इन्हें काफी अच्छा अच्छा माना जाता है। लेखिका अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेषज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में लोकप्रिय है ।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह संस्था पर अहम फैसले

यह एक हकीकत है कि आधुनिक जीवन में रिश्तों में स्वतंत्रता की बयार स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता से परवान चढ़ी है लेकिन भारत जैसे परंपरावादी समाज में सदियों से विवाह एक अनुबंध होने के साथ-साथ एक गहरी सामाजिक मान्यता भी है। यह भी एक सत्य है कि वयस्कों के रिश्तों को संरक्षण या मान्यता से वंचित करना, ऐसे रिश्तों को समाप्त नहीं करता है। वास्तव में यह केवल उन्हें असुरक्षा और कानूनी अनिश्चितता की ओर धकेल देता है। सही मायनों में आवश्यकता न्यायिक असंगति की नहीं है, बल्कि विधायी स्पष्टता की ही है। वास्तव में एक हकीकत यह भी है कि भारतीय समाज में वैवाहिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने वाले एक प्रभावी ढांचे की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

आमतौर पर दुनियाभर में न्यायपालिका को रूढ़ीवादी फैसलों को अहमियत देने वाला माना जाता रहा है। भारत में भी कुछ ऐसा ही रहा है। आजादी के कुछ दशकों बाद तक ऐसा रहा, पर इधर कुछ सालों से भारतीय न्यायपालिका ने ऐसे फैसले सुनाए है जिन्हें बेशक प्रगतिशील फैसले कहा जा सकता है। जाहिर है कि ऐसे फैसले सामाजिक बदलाव की दिशा में एक अहम कदम साबित होते हैं। इसी हफ्ते मेघालय हाईकोर्ट के एक फैसले में कहा गया कि रोमियो-जूलियट कैटेगिरी के मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों को रद्द किया जा सकता है। खासकर जब दो किशोरों के बीच सहमति से संबंध हो। इसी तरह हाल ही में इलाहबाद हाईकोर्ट ने साफ किया कि शादीशुदा शख्स भी किसी एडल्ट के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है, बशर्ते वो सहमति के साथ हो। इन दोनों फैसलों से साफ झलकता है कि कोर्ट प्यार और रिश्तों को जुर्म की कैटेगरी से बाहर रखने के पक्ष में है। इसमें ये भी साफ होता है कि अदालत व्यक्तिगत गरिमा को प्रोटेक्शन देने के पक्ष में है। ऐसे फैसले समाज की पारंपरिक मानसिकता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहबाद हाईकोर्ट ने दो मामलों में ऐसा फैसला दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मूल अधिकारों का जिक्र किया। साथ ही जोड़े की सुरक्षा की बात कही। वहीं, लव मैरिज के मामले की सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने कहा कि प्रेम विवाह को जोड़ा सम्मान का मुद्दा नहीं बना सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन में रह रहे जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मूल अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा है कि अंतर्धार्मिक कपल की सुरक्षा आवश्यक है। सोनभद्र के अंतर्धार्मिक कपल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि उन्हें अपने परिजनों से खतरा है। पुलिस से संपर्क करने पर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति से अगर वयस्क जोड़े सहमति से लिव-इन में रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के साथ-साथ वर्ष 2021 के विशेष अधिनियमों का जिक्र करते हुए कहा कि लिव-इन में रहना किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है। हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशन किसी भी मौजूदा कानून के तहत न प्रतिबंधित है और न ही दंडनीय। याचिकाकर्ताओं ने कोई कानूनी अपराध नहीं किया है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा देने करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दर्जा संवैधानिक व्यवस्था में सबसे ऊपर है। दरअसल, भारतीय कानून ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में, परंपरागत भारतीय समाज में लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता देने की दिशा में सावधानीपूर्वक ही कदम बढ़ाया है। इसके बावजूद भी यह विवाह को एक कानूनी रूप से स्वीकृत संस्था के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है। जिसके अंतर्गत वयस्कों के अपने अधिकार और दायित्व भी हैं। निर्विवाद रूप से, जिन्हें आसानी से दरकिनार भी नहीं किया जा सकता है। इस परिणाम के मूल में एक न्यायिक विसंगति भी है। जहां न्यायालय लिव-इन रिलेशन को अपराध की श्रेणी से तो बाहर कर देता है, लेकिन उसके परिणामों को वैध ठहराने से हिचकिचाता है। दरअसल वयस्कों के रिश्तों में यह तनाव सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। निर्विवाद रूप से आज भारतीय समाज एक बड़े संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है। जिसमें भारतीय परंपरागत जीवन मूल्यों तथा तेजी से बदलते रिश्तों के बीच का एक द्वंद्व भी शामिल है। यह एक हकीकत है कि आधुनिक जीवन में रिश्तों में स्वतंत्रता की बयार स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता से परवान चढ़ी है लेकिन भारत जैसे परंपरावादी समाज में सदियों से विवाह एक अनुबंध होने के साथ-साथ एक गहरी सामाजिक मान्यता भी है। यह भी एक सत्य है कि वयस्कों के रिश्तों को संरक्षण या मान्यता से वंचित करना, ऐसे रिश्तों को समाप्त नहीं करता है। वास्तव में यह केवल उन्हें असुरक्षा और कानूनी अनिश्चितता की ओर धकेल देता है। सही मायनों में आवश्यकता न्यायिक असंगति की नहीं है, बल्कि विधायी स्पष्टता की ही है। वास्तव में एक हकीकत यह भी है कि भारतीय समाज में वैवाहिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने वाले एक प्रभावी ढांचे की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जाती रही है। हमें मौजूदा परिदृश्य में यह बात स्वीकार करनी होगी कि यद्यपि विवाह संस्था संरक्षण की हकदार है, फिर भी पुरुष या स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक इसके अधीन बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अंततः कानून को एक सरल सत्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि जब रिश्ते टूट जाते हैं तो व्यक्तियों को गरिमा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देना हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिये खतरा नहीं है। बल्कि यह उसका एक आवश्यक अनुकूलन ही है। ऐसे समय पर जब तकनीक व सूचना क्रांति से पूरी दुनिया एक संस्कृति में ढल रही है, हम अलग-थलग नहीं रह सकते। हमें पीढ़ियों के अंतराल से उपजी सोच का भी सम्मान करना होगा। लिव-इन रिलेशन पर ये फैसला उन कपल्स के लिए राहत है जो पारिवारिक दबाव या सामाजिक कलंक से गुजर रहे हैं। दोनों फैसलों से एक बात उभरती है कि कोर्ट अधिकतर मामलों में प्रेम को अपराध की बजाय मानवीय भावना मान रहा है। प्यार को लेकर जज संविधान के आर्टिकल 21 को सही मायने में समझ रहे हैं। समय-समय पर न्यायपालिका को ऐसे फैसले नजीर बन जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें बहुमत की भावनाओं को देखते हुए ऐसे कानून कभी नहीं बना सकतीं जिन्हें समाज पचा न सके। इलाहाबाद और मेघालय हाईकोर्ट का फैसला इस मामले में ऐतिहासिक है। ये फैसले समाज के लिए चुनौती से भरे क्यों हैं, क्योंकि भारतीय समाज अभी भी पारंपरिक परिवार व्यवस्था, जाति-धर्म और नैतिकता के घेरे में बंधा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, [illegible] एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

जिला परिषद से संबंधित विकास कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करवाए संबंधित अधिकारी - मोनिका दहिया

सोनीपत । जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका दहिया ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से एसडीओ/जेई को निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों के एस्टीमेट जल्द से जल्द तैयार कर विभाग को भिजवाएं, ताकि कार्यों को शीघ्र गति दी जा सके। श्रीमति मोनिका दहिया की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद सोनीपत सदन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन जिला परिषद हॉल में किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो विकास कार्यों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री का भी विशेष ध्यान रखे, कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी न मिलने पाए। उन्होंने अधिकारियो को निर्देश दिए कि जिला परिषद से होने वाले किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित पार्षद को अवगत करवाए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के तहत आने वाले सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और आमजन को इनका लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर किसी भी पार्षद को किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर वो उनसे सम्पर्क करे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जिला परिषद से संबंधित कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान डीडीपीओ मनीष मलिक, रोडवेज जीएम संजय सिंह, एक्सीईन पंचायती राज कुलबीर, बीडीपीओ राजेश व दिगंबर व अन्य सभी संबंधित अधिकारी व पार्षदगण मौजूद रहे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिला की मंडियों का किया निरीक्षण

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को जिला रोहतक में महम, रोहतक व सांपला मंडियों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकार किसानों की फसल खरीद प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में फसल आवक के चलते मंडियों में अत्यधिक व्यस्तता है, लेकिन प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसानों व आढ़तियों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में बारदाने की कोई कमी नहीं है और फसल उठान में हो रही दिक्कत को भी दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते दबाव को देखते हुए गेट पास प्रणाली में सुधार किया गया है। अब एंट्री और आउटसाइड गेट पास को अलग-अलग कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति में सुधार होगा और कार्य तेजी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसल का सीजन

अब कम समय में सिमट गया है, जिससे एक साथ अधिक मात्रा में फसल मंडियों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। इन व्यवस्थाओं से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था एक बड़ा सुधार है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों को सीधा लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्णय लिए जाते हैं, ताकि सभी हितधारकों को लाभ मिल सके। मंडियों में खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ओलावृष्टि और बारिश से फसल को हुए नुकसान के संदर्भ में कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों को हुए नुकसान की सूचना मिलने पर सरकार द्वारा इसका आंकलन करवाकर किसानों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फसल सीजन से पहले ही मंडियों में पक्के रास्ते, शेड और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को फसल बिक्री के

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

-प्रदेश सरकार फसल खरीद प्रक्रिया को सुचारू व पारदर्शी बनाने के लिए है प्रतिबद्ध

दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि वे अब तक पंचकूला, अंबाला, जींद, रोहतक, पानीपत सहित कई जिलों की मंडियों का दौरा कर चुके हैं और पूरे अप्रैल माह में निरीक्षण जारी रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल खरीद, उठान और भुगतान प्रक्रिया को और अधिक तेज व सुचारू बनाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि किसी मंडी में तोल या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत मिलती है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा जिला स्तर पर की गई विशेष प्रचार अभियान की शुरूआत

सोनीपत । (संवाददाता) सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर विशेष प्रचार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त नेहा सिंह ने हरी झण्डी दिखाकर प्रचार वैन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपनी सशक्त भूमिका निभा सकें। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वरोजगार, सुरक्षा एवं सामाजिक सम्मान जैसे विषयों पर महिलाओं को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह विशेष प्रचार अभियान शुरू किया गया है, जो जिला के गांव-गांव तक पहुंचकर महिलाओं को योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को पूरी गंभीरता व प्रभावशीलता के साथ संचालित किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक गांव में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी हो और उन्हें

योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि महिलाओं को किसी भी योजना का लाभ लेने में कोई कठिनाई न हो और उन्हें समय पर उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। इस अवसर पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राकेश गौतम ने बताया कि अभियान के तहत विभागीय भजन व सांस्कृतिक पार्टियां गांव-गांव जाकर लोकगीत, नुक्कड़ नाटक व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से

***उपायुक्त नेहा सिंह ने हरी झण्डी दिखाकर किया प्रचार वैन को रवाना**

***विभागीय भजन व सांस्कृतिक पार्टियां गांव-गांव जाकर करेंगी महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई गई योजनाओं का प्रचार-प्रसार-डीआईपीआरओ राकेश गौतम**

नारी शक्ति वंदन अभियान व महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगी। ताकि यादा से यादा महिलाएं पात्र योजनाओं का लाभ उठा सके।

हरियाणा में पूर्व सैनिकों एवं परिवारों के लिए समर्पित कॉल सेंटर स्थापित

चंडीगढ़ । हरियाणा के पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के कर्मियों तथा उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान तथा विभिन्न योजनाओं के संबंध में उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेन्द्र कुमार ने बताया कि पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के कर्मियों तथा उनके परिजनों को विभिन्न सेवाओं, योजनाओं एवं सुविधाओं से संबंधित जानकारी सहज एवं शीघ्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए समर्पित कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।

मण्डियों व खरीद केन्द्रों पर आने वाले गेंहू का योजनाबद्ध तरीके से तुरंत करवाएं उठान-उपायुक्त नेहा सिंह

(संवाददाता)

सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने अधिकारियों व खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि मण्डियों व खरीद केन्द्रों पर आने वाले गेहूं का योजनाबद्ध तरीके से तत्काल उठान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि फसल की आवक बढ़ने के साथ ही परिवहन, भंडारण और लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था पहले से ही सुदृढ़ रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा में उठान प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि, मण्डियों में जाम की स्थिति न बने और किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान मिल सके।

***-गेंहू में आग लगने की घटना होने पर संबंधित अधिकारी तुरंत मुख्यालय भेजे रिपार्ट, ताकि किसानों को मिल सके मुआवजा**

***-सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र की मण्डियों और खरीद केन्द्र का समय-समय पर करें निरीक्षण, ताकि किसानों को न आए कोई समस्या**

***-गेंहू की खरीद व उठान की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता ने वीसी के माध्यम से उपायुक्तों के साथ की बैठक**

गेंहू की खरीद व उठान की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता ने वीसी के माध्यम से उपायुक्तों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त नेहा सिंह ने उन्हें अवगत करवाया कि जिला में गेंहू की खरीद व उठान सुचारू रूप से करवाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हर स्थिति पर वे स्वयं नजर बनाए रखे है कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत उनके द्वारा एक्शन लेते हुए उस समस्या का तुरंत समाधान करवाया जाता है। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि गेहूं में आग लगने की किसी भी घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करें और बिना देरी किए विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि फायर ब्रिगेड व अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे नुकसान को न्यूनतम किया जा सके और किसानों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र की मण्डियों एवं खरीद केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान खरीद प्रक्रिया, उठान, साफ-सफाई, पेयजल, छाया एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो। उपायुक्त ने अधिकारियों को किसानों से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, सुचारू एवं किसान हितैषी बनी रहे।

सीबीएसई बोर्ड 10वीं सेशन-1 का रिजल्ट जारी- 93.70फीसदी हुए पास, लड़कियां फिर आगे, त्रिवेंद्रम रीजन टॉप पर; 15 मई से होंगे सेशन 2

नई दिल्ली । सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं सेशन - 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99फीसदी है, जबकि लड़कों का रिजल्ट 92.95फीसदी दर्ज किया गया है। ट्रांसजेंडर छात्रों ने भी इस बार 91.30फीसदी रिजल्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। 99.75फीसदी के साथ त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट बेस्ट रहा है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in और उमंग एप पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स इस साल सीबीएसई बोर्ड 10वीं के सेशन 1 परीक्षा में शामिल हुए हैं जिनका रिजल्ट जारी किया गया है।

मेरिट लिस्ट नहीं होगी जारी

सीबीएसई बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है। इसके अलावा रिजल्ट में कोई टॉपर भी घोषित नहीं किया जाता है। बोर्ड सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को ये निर्देश भी देता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल या जिले का टॉपर घोषित न करें।

नए टू बोर्ड सिस्टम के तहत हुई एग्जाम

इस साल सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की एग्जाम नए टू बोर्ड सिस्टम के तहत आयोजित की है। पहला बोर्ड एग्जाम (अनिवार्य) - 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 को हुआ था। वहीं दूसरा बोर्ड एग्जाम (ऑप्शनल) है जो 15 मई से 1 जून 2026 तक होगा।

15 मई से होंगे सीबीएसई 10th सेशन 2 एग्जाम

10वीं बोर्ड सेशन - 2 एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। इसमें अधिकतम 3 अंकों में सुधार का मौका मिलेगा। इसके अलावा 2 विषयों में फेल छात्रों को कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा गया है, जो दूसरी एग्जाम दे सकते हैं। तीन या इससे ज्यादा सब्जेक्ट में फेल छात्रों को 2027 की मेन एग्जाम देनी होगी।

33फीसदी पासिंग मार्क्स जरूरी

सीबीएसई 10वीं सेशन - 1 की परीक्षाओं में पास होने के लिए, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों में न्यूनतम 33फीसदी अंक लाना जरूरी है। इस साल 10वीं बोर्ड सेशन - 1 एग्जाम देश के 8 हजार से ज्यादा एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल

सीबीएसई 10वीं सेशन - 1 की परीक्षा इस साल 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने दी थी। इस साल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अलग-अलग जारी होंगे। इसे लेकर बोर्ड ने कोई क्लेरिफिकेशन जारी नहीं किया है।

मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सम्राट ने छुए नीतीश के पैर

गृह समेत 29 विभाग संभालेंगे सीएम सम्राट चौधरी- जेडीयू के पास 18 विभाग

पटना । सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार की नई सरकार में जदयू से विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग रहेंगे। विजय चौधरी को 10 और बिजेंद्र यादव को 8 विभाग मिले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यही विभाग बाकी मंत्रियों में बंटेंगे। तब तक तीनों मंत्री ही इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री के पिता शकुनी चौधरी ने कहा, कभी-कभी ईश्वर की कृपा होती है। इतने कई पार्टियों के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश की कृपा से सम्राट आगे बढ़ गया। मेहनत रंग लाती है जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा।'

पीएम मोदी की सीएम सम्राट चौधरी को बधाई, कहा- बिहार के विकास को नयी दिशा और गति देगा चौधरी का जमीनी अनुभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भाजपा नेता सम्राट चौधरी को बधाई दी और कहा कि उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी स्तर का अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। प्रधानमंत्री ने राज्य के उपमुख्यमंत्री के तौर पर विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के शपथ लेने पर उन्हें भी बधाई दी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं! उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में जनता-जनार्दन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बिहार चौतरफा विकास की नयी ऊंचाइयों को छूएगा। उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को भी बधाई देते हुए लिखा, बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विजय कुमार चौधरी जी और बिजेंद्र प्रसाद यादव जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं! मुझे पूरा भरोसा है कि इनका जमीनी अनुभव और जनहित को लेकर प्रतिबद्धता बिहार के विकास को नयी दिशा और गति देगी। इनके साथ ही राज्य सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के नित-नये मानक

होर्मुज पर नरम पड़े ट्रंप, ईरान के साथ 2 हफ्ते और सीजफायर बढ़ाने पर बन सकती है सहमति

नई दिल्ली। होर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड के बीच राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर ईरान को लेकर थोड़े नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं. पाकिस्तान के दोबारा ईरान के साथ बैठक होने की खबरों के बीच अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच दो हफ्ते और सीजफायर बढ़ सकता है. स्टेट ऑफ होर्मुज और परमाणु हथियारों के मामले पर दोनों ही देशों के बीच तकरार बढ़ गई थी, लेकिन इस ताजा घटनाक्रम से तनाव कम होने की उम्मीद की जा रही है. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को बढ़ाने के मामले पर अहम अपडेट मिला है. मध्यस्थों की कोशिशों में प्रगति हुई है, क्योंकि उम्मीद है कि दोनों विरोधी पक्ष जल्द ही बातचीत कर सकते हैं. अमेरिका-ईरान ने सीजफायर बढ़ाने के मामले पर सहमति भी जता दी है. अगर दोबारा दोनों देशों के बीच बात हुई तो तीन मुद्दे शामिल होंगे. इसमें पहला मुद्दा परमाणु कार्यक्रम का है. वहीं दूसरा पॉइंट स्टेट ऑफ होर्मुज से जुड़ा है. तीसरा मुद्दा मुआवजे को लेकर है. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के करीब है. उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर वे अभी पीछे हट जाएं, तो ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे. ट्रंप का यह रिएक्शन उस बयान के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें 'यूएस सेंट्रल कमांड' ने कहा था कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों से आने-जाने वाले सभी यातायात को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है. ट्रंप ने ईरान के मसले पर हाल ही में चीन से भी बात की. उन्होंने कहा, मैंने शी जिनपिंग को पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि ईरान को हथियार न दे, उन्होंने भी मुझे चिट्ठी लिखकर कहा कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं. अगर उनके पास परमाणु हथियार है, तो हमें कुछ समय तक उनके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कब तक टिक पाएंगे.

विपक्ष करेगा महिला आरक्षण बिल का विरोध

मल्लिकार्जुन खरगे बोले- नीयत में खोट है, यह सिर्फ चुनावी पैंतरा

नई दिल्ली । देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से इसे लागू करने की योजना बना रही है, वह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और जनता को गुमराह करने वाला कदम है। मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद कहा, हम सभी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से इसे लेकर आई है, वह राजनीति से प्रेरित है। हमने हमेशा इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन हमारा आग्रह है कि पुराने संशोधनों को लागू किया जाए। सरकार परिसीमन और जनगणना के नाम पर चालें चल रही है। कार्यपालिका के जरिए संविधान की उन शक्तियों को हथिया रही है जो संसद और संस्थाओं के पास होनी चाहिए। इन्होंने पहले भी असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन में हमें धोखा दिया है। इसलिए हम इस बिल के मौजूदा स्वरूप का एकजुट होकर संसद में विरोध करेंगे।वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन हम इस बिल के साथ जोड़ी गई परिसीमन की प्रक्रिया के पूरी तरह खिलाफ हैं। उनका कहना है कि आरक्षण को परिसीमन और जनगणना की शर्तों में उलझाना सरकार की एक सोची-समझी चाल है, जिससे इस अधिकार को लंबे समय तक टाला जा सके, इसलिए विपक्ष महिलाओं को हक देने का तो पक्षधर है लेकिन सरकार के इस तरीके का पुरजोर विरोध करता है।

नोएडा हिंसा के बीच सीएम योगी की दो टूक- फैक्ट्रियों में बाहरी तत्वों का दखल बर्दाश्त नहीं, बिगाड़ने वाले बहुत आएंगे पर बनाने वाले कम

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैक्ट्रियों के कामकाज में किसी भी बाहरी तत्व को दखल देने की अनुमति नहीं देने की सलाह देते हुए बुधवार को कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप से शांति और प्रगति में बाधा आ सकती है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स के संयंत्र से 10 लाखवीं गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और आगजनी के दो दिन बाद की है। नोएडा में बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों समेत फैक्ट्री मजदूरों ने वेतन में वृद्धि तथा अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए काम बंद कर दिया था। कुछ जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था जिसके चलते आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं। आदित्यनाथ ने इससे पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के पीछे साजिश की आशंका भी जताई थी, जिसकी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में टाटा मोटर्स के 34 साल के सफर एक गौरवपूर्ण यात्रा बताया। उन्होंने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और कर्मचारियों तथा दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में हमारी फैक्ट्रियों या समूहों के आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी तत्व को दखल देने की इजाजत न मिले। बिगाड़ने वाले बहुत आएंगे, बनाने वाले कम मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राज्य और समाज आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोगों में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उन संस्थानों और संगठनों का आभारी रहना चाहिए जो रोजगार के अवसर, बच्चों को शिक्षा और युवाओं के विकास के मौके मुहैया कराते हैं और ऐसा करके वे लोगों की जिंदगी संवारने और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। टाटा समूह के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस कम्पनी ने हजारों परिवारों को रोजी-रोटी कमाने में मदद की है और उनके बच्चों की शिक्षा और प्रगति में सहयोग दिया है। आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे संस्थानों की वजह से ही युवा अपना करियर बना पाते हैं, समाज में सम्मान पाते हैं और अपनी पहचान बनाए रख पाते हैं। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता का यह भाव इसलिए जरूरी है क्योंकि यह व्यक्तियों और समाज, दोनों को मजबूत बनाता है और लंबे समय तक चलने वाले विकास और भरोसे को बनाए रखने में मदद करता है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स संयंत्र में 10 लाखवीं गाड़ी बनाने की उपलब्धि हासिल करने में योगदान के लिए टाटा के कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में बनी बसें आम लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने का काम जारी रखेंगी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन, टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक गिरीश वाघ समेत कई लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाखवें वाणिज्यिक वाहन को हरी झंडी दिखाना सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं, बल्कि यह भारत के उदय और एक वैश्विक विनिर्माण हब के तौर पर उत्तर प्रदेश की तैयारी को भी दिखाता है। राज्य के जनसांख्यिकीय लाभ पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कुल श्रमशक्ति में 56 प्रतिशत से ज्यादा युवा शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के मुताबिक उन्हें कार्यकुशलता, नवाचार और प्रौद्योगिकी से जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि टाटा समूह ने स्टील और ऑटोमोबाइल से लेकर सॉफ्टवेयर और आतिथ्य तक अलग-अलग क्षेत्र में राष्ट्र-निर्माण में अपने योगदान और गुणवत्ता के जरिये लोगों का भरोसा जीता है। दिवंगत रतन टाटा के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स के संयंत्र की स्थापना से हजारों लोगों को सीधे तौर पर और उससे भी अधिक लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिला है।

छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसा- अब तक 19 की मौत- 36 लोग झुलसे

सक्ती । छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट हादसे में अब तक 19 मौतें हो चुकी हैं। 4 की मौके पर ही जान गई, जबकि 13 की मौत रायगढ़ के अलग-अलग अस्पतालों में हुई। 2 की मौत रायपुर के कालड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। प्लांट में मंगलवार दोपहर बॉयलर ब्लास्ट हो गया था। मृतकों में 4 छत्तीसगढ़ से हैं, जबकि बाकी 15 यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से हैं। हादसे में कुल 36 लोग झुलसे हैं, 18 घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। हादसे के बाद प्लांट के बाहर मजदूरों के परिजन ने हंगामा किया। उन्होंने प्रबंधन पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। कुछ मजदूर लापता हैं। परिजन का कहना है कि प्रबंधन कोई जानकारी नहीं दे रहा है। वहीं कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वेदांता प्रबंधन ने मृतक परिजन को 35-35 लाख रुपए सहायता राशि और नौकरी देने का ऐलान किया है। घायलों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले पीएमओ ने मुआवजे की घोषणा की थी। PMNRF से हर मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए देने का ऐलान किया।

आंध्र प्रदेश में संदिग्ध धमाका, चार की मौत, 18 घायल; इलाके में चारों तरफ मची अफरा-तफरी

अमरावती । आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिला में बुधवार को एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह धमाका इतना तेज था कि आसपास के कम से कम दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। शुरुआती जांच में इसे गैस सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा था, लेकिन धमाके की तीव्रता को देखते हुए पुलिस को शक है कि मामला सिर्फ सिलेंडर विस्फोट तक सीमित नहीं हो सकता। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। उस घर में उस समय कई मजदूर रह रहे थे, जो मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि धमाके की असली वजह क्या थी।

केंद्रीय बलों ने हवाई अड्डा जाते समय मेरी कार की तलाशी लेने की कोशिश- ममता बनर्जी

बंगाल । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि जब वह दिन में कोलकाता हवाई अड्डा जा रही थीं, तभी केंद्रीय बलों ने उनकी कार की तलाशी लेने की कोशिश की। मुख्यमंत्री से पहले, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने उसके नेताओं के वाहनों की गहन तलाशी लेने का आदेश दिया है। बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केंद्रीय बलों में हिम्मत है, तो वे हर दिन उनकी कार की जांच कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं आज कोलकाता हवाई अड्डा जा रही थी तो केंद्रीय बलों ने मेरी कार की तलाशी लेने की कोशिश की। अगर आपमें हिम्मत है, तो आप हर दिन मेरी कार की जांच करें। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि केवल उसके नेताओं, विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी के वाहन की निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आधार पर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा सघन तलाशी के लिए चुना गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा, इस तरह की गहन जांच के लिए केवल उनकी पार्टी के नेताओं को ही क्यों चुना जा रहा है जबकि अन्य को बख्शा जा रहा है यह चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का एक स्पष्ट मामला है। तृणमूल के आरोपों पर निर्वाचन आयोग की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होना है, जबकि मतगणना चार मई को होगी।

टीएमसी से पाई पाई वसूल करेगी बीजेपी- शाह

बंगाल । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संकल्प जताया कि भाजपा, तृणमूल कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से बंगाल की जनता से लूटी गई एक-एक पाई वसूल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर दो दशकों तक सत्ता में रहने के बाद भी भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सत्ता से जाना निश्चित है, लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने का काम राज्य के उत्तरी क्षेत्रों से शुरू होगा। शाह ने कहा, मोदी ने गुजरात पर 12 साल शासन किया और केंद्र में भी पिछले 12 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, फिर भी उनके खिलाफ एक पैसे तक का किसी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। शाह ने रैली में कहा,बंगाल में भाजपा को सत्ता में लाएं और तृणमूल नेताओं द्वारा लोगों से लूटे गए एक-एक पैसे को ब्याज समेत वसूला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आने के बाद तृणमूल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले में 300 करोड़ रुपये हड़पे और उत्तर बंगाल के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत बाढ़ राहत कोष से 100 करोड़ रुपये चुराए। शाह ने कहा, उत्तर बंगाल तीन टी के लिए जाना जाता है-टी (चाय), टिंबर (लकड़ी) और टूरिज्म (पर्यटन)। लेकिन ममता बनर्जी ने इसमें एक चौथा टी जोड़ दिया है-भाजपा कार्यकर्ताओं के टीअर्स (आंसू), जिन्होंने तृणमूल के गुंडों के हाथों असहनीय पीड़ा झेली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद सरकार तृणमूल के गुंडों को खोजने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने का अपना काम पूरा करेगी। उत्तर बंगाल केंद्रित कई विकास योजनाओं की घोषणा करते हुए शाह ने कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद पार्टी चाय बागान श्रमिकों को भूमि स्वामित्व प्रदान करेगी, जिससे वे भूखंडों के मालिक बन जाएंगे। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में भी इन योजनाओं का वादा किया है।

अशोक मित्तल पर ईडी का एक्शन, अरविंद केजरीवाल बोले- बर्दाश्त नहीं करेंगे, करारा जवाब देंगे

नई दिल्ली ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल से जुड़े व्यावसायिक संस्थानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत छापेमारी की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. व्यवसायी और शिक्षाविद् मित्तल (61) को हाल में राज्यसभा में आप का उपनेता नियुक्त किया गया है, जहां उन्होंने राघव चड्ढा की जगह ली है. अशोक अपने नाम पर एक विश्वविद्यालय समेत लवली ग्रुप का नेतृत्व करते हैं. अधिकारियों के अनुसार, मित्तल से जुड़े कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जालंधर और फगवाड़ा सहित कुछ अन्य स्थानों पर तलाशी ली जा रही है. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की जा रही है. उधर, आप सांसद अशोक मित्तल के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, बीजेपी लगातार विपक्षी दलों को परेशान कर रही है. जहां भी विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां या तो ईडी को भेजा जाता है या फिर सीबीआई को. बहरहाल, बीजेपी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी छापेमारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी "तैयारियां" शुरू कर दी है, जहां फिलहाल 'आप' की सरकार है.

आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि बीजेपी ने पंजाब में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वह ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिए बिना चुनाव लड़ सकती है वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि राज्यों में चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के राजनीतिक दौरे होते हैं. उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उस पर निरंकुश तरीके से काम करने का आरोप भी लगाया. बहरहाल, अधिकारियों का कहना है कि यह छापेमारी फेमा के तहत चल रही जांच का हिस्सा है और मित्तल से जुड़े विभिन्न कारोबारी परिसरों की तलाशी ली जा रही है.